

22 Jan 2022

Subject Teacher

Adv. Rajendra Rathore (+91 702 3065 394)

35 - Old Chambers

107 in Nobel Chambers

Recommend book - Suryanarayan Mishra

Payment of wages Act, 1936

Enforcement of this Act on 28 March 1937

Wage - धन के रूप में अभिव्यक्त होने वाली मज़दूरी जिस से नियोजन संविदा में अभिव्यक्त या विवक्षित वर्णित सभी निबंधन/ शर्तों की पूर्ति करता हो।

(धन के रूप में अभिव्यक्त पारिस्त्रमिक)

(जिस का मतलब धान की मंडी।)

जीवन निर्वाह सूचकांक = life index

Before bonus Act the bonus was not a part of wages but after the bonus Act it become part of wages. If the bonus is provided in form of profit (लाभांश) is not a part of wages.

HRA - मज़दूर का हिस्सा है

यात्रा भत्ता भी मज़दूर का हिस्सा नहीं है। जो कार्य के लिए के यात्रा हो।

Overtime is also a part of wage.

8.33% of salary part has to be given as bonus.

Who is responsible to pay?

Manager or employer (नियोजक) or the person who has made a contract with you (contractor)

नियोजक सीधा payment कर सकता है।

नियोजक की जानकारी के बिना भी नियुक्ति हो सकती है। कैसे? किसी agency के द्वारा किसी श्रमिक की नियुक्ति करना।

Duration - monthly basis should be done. The employer has to pay the wages within the 7 days of last 30 days of work.

In case of state govt it can be 10 days and it can extend to 15 days (in exceptional case)

Time - The payment has to be made only on working days and in working hours.

Mode of payment - प्रचलित currency (sec 3 to 6)

After amendment आपके निवेदन पर लिखित आवेदन पर किसी वित्तिय संस्था में जमा करवा सकते हैं। e.g. bank

28 Jan 2022

अगर किसी factory मज़दूर की सेवा समाप्त कोई employer करता है तो उनका भुगतान 2 दिन के भीतर करना होगा।

jins के रूप में भुगतान होता है तो उसके value पहले से ही तय की जाएगी।

jins का अर्थ है खाध्यान

Deduction (कटौती) - मज़दूरी बिना किसी कटौती के अदा की जाएगी।

कटौती जैसे PF, यदि लिख कर दे की सदस्यता के लिए इत्यादि।

निलम्बन, अनुपस्थिती या जुर्माना ये कटौतियाँ वैध हैं।

15 वर्ष तक की आयु के मज़दूर का कोई जुर्माना नहीं काटा जाएगा।

जुर्माना (Fine) sec 8

अनुपस्थिती sec 9

10 या अधिक एकमत हो कर बिना सूचना के अनुपस्थित रहते हैं तो उनके अनुपस्थिती पर 8 दिन से ज़्यादा की मज़दूरी नहीं काटी जाएगी।

अवैध हड़ताल में शामिल होने पर मज़दूरी काटी जाएगी।

29 Jan 2022

Sec 14 - Inspector - there is 2-3 procedure of appointment

किसी कारख़ाने का inspector

किसी कारख़ाने से railway में हो

समुचित सरकार जिसे चाहे जिसे उचित समझे उसे inspector बना सकती है

निरीक्षण - किसी भी कारख़ाने के निरीक्षण कर सकता है। निरीक्षक को हर उद्योग इस अधिनियम के तहत कुछ सुविधाएँ देगा। निरीक्षण, जाँच इत्यादि।

Sec 15 - inspector ने निरीक्षण किया तो वो एक पक्षकार हो गया है। The authority can be anyone as per workman compensation or district judge or commissioner or some other state authority with two years of experience etc are the authorities (any one) to whom the inspector will submit his report.

Gazette notification से inspector का jurisdiction decide करते हैं।

Sec 16 claim application

Sec 17 appeal

Sec 18 Powers of authority - Collect evidence, issue a summon for witnesses or to produce documents.

Sec 19 Omitted

Sec 20 Penalty

Wage definition, mode of payment is very important for exam perspective.

3 Feb 2022

MINIMUM WAGES ACT, 1948

Adolescent (कुमार) means a person who has completed his 14th year of age but not completed his 18 year

कुमार - ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी आयु के 14 वर्ष पूर्ण कर लिए हों एवं 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुए हों

Adult - who has completed his 18 years of age.

Child means a person who has not completed 14 years of his age.

Appropriate govt सम्मूचित सरकार - जहां सेंट्रल govt ने railway खान या oil field या और किसी निगम की स्थापना की गई है वह सम्मूचित सरकार से केंद्र सरकार से है।

इनके अतिरिक्त किसी और रोजगार में सम्मूचित सरकार राज्य सरकार कहलाएगी।

Competent Authority - means the authority appointed by appropriate govt by notification in the official gazette.

वह प्राधिकारी जो सम्मूचित सरकार द्वारा राज पत्र अधिसूचित कर किया जाता है

Employer नियोजक (**important**) - any person who employs whether directly or through another person or whether on behalf himself or any other person.

ऐसा व्यक्ति जो किसी को नियोजन में रखता है प्रत्यक्ष रूप से अथवा अन्य व्यक्ति के माध्यम से स्वयं के द्वारा या अन्य व्यक्ति द्वारा।

Employee - means any person who is employed for hire (अवक्रय) (किराये पर) or reward to do anyone skilled or unskilled, manual or electrical in a scheduled employment in respect of which minimum rate of wages fixed.

4 Feb 2022 - Preeti Bapna Ma'am 8764 123 557

124 - Nobel Chambers

Maternity Act 1961

State govt को यह शक्ति दी गई है की वह केंद्र सरकार की आज्ञा से दो माह का gazette अधिसूचना निकाल कर उपयुक्त प्रतिस्थान पर यह अधिनियम लागू कर सकती है

Sec 2 Applicable to whom - Every factory, mines, plantation, established by govt. acrobatic (circus) or any other performance. Every shop, establishment, in which 10 or more than 10 person (worked with in 12 months).

Object - जो महिलायें कार्य कर रही ही उनके लिए नियम बनना। ताकि वो child होने के पहले एवं होने के बाद उसका ध्यान रख सके।

Restriction on employment by women: To protect her and her unborn child.

1 Month + 8 Week <= Expected due date / Actual delivery date => 8 Week

It is because, if she does hard work then she has adverse effect on her health.

Delhi vs Female worker, AIR 2000 SC 1274

जो भी महिला कार्य कर रही है उन्हें कोई कठिन कार्य नहीं कर सकता क्योंकि इस से उनकी सेहत व गर्भ पर प्रभाव पड़ेगा। इसी कारण से इस अधिनियम में यह नियत किया गया की गर्भवती को थोड़े वक्त के लिए छुट्टी मिलेगी। delivery के पहले भी और बाद में भी।

Sec 5 Right to payment of maternity benefit: Employer calculate the average of last 3 months of her wages before her maternity leave.

If a woman she is working in established organisation then if she worked for the 80 days in a year then she is eligible for the maternity benefit.

माता भी सही है और संतान भी स्वस्थ है तो ये 26 सप्ताह का maternity benefit दोनों को मिलेगा

अगर माता जिंदा है एवं बच्चा नहीं रहा तो माता को मिलेगा

माता की मृत्यु हो गई है एवं बच्चा जीवित है तो इसका जो nominee या legal representative होगा उसको ये सारा बेनिफिट मिल जाएगा

अगर दोनो की मृत्यु हो गई तो भी nominee को मिलेगा या सारा फ़ायदा.

Sec 8 Medical bonus - Rs. 1000 will get as a medical benefit.

2016 amendment - increase paid maternity leave from 12 week to 26 week. Before delivery 8 week remaining after delivery

Adopt (गोद लेने वाले माता के लिए अगर बच्चा अगर तीन महीने से कम उमर का है तो दत्तक माता को 12 महीने की मिलेगी)

Surrogate mother - 12 week benefit

Work at home provisions - after 26 week of leave, if she needs leave then she can work from home.

क्रेच (creche) - जाह पचास या अधिक कर्मचारियों को रोज़गार देने वाले प्रतिएक प्रतिस्थान के लिए क्रेच सुविधा को अनिवार्य बनाना है। Mother can meet her child for 4 times in a day. (दिन में चार बार शिशु ग्रह में जाने की अनुमति है)

5 Feb 2022

Sec 10 - **Pregnancy time में अगर कोई lady बीमार हो गई है तो उसे advance में उसे छुट्टी मिल सकती है।**

Sec 11 - Nursing break - कार्य करने वहली महिला delivery के बाद वापस कार्य पर लौट ती है तो उसे दो interval मिलेंगे। जब तक बच्चा पंद्रह महीने का नहीं हो जाता है

Sec 11(a) Creche facility

Sec 12 - जब कभी गर्भवती महिला maternity benefit ले रही है उस समय वह कार्य में अनुपस्थित है तो नियोक्ता उसे नौकरी से निकाल नहीं सकता

एसी महिला के लिए शर्तों को नहीं बदल सकता

अगर उसे नौकरी से हटा दिया है तो भी उसे bonus और maternity benefit मिलेंगे

यदि कोई गर्भवती महिला कुछ ऐसे कार्य करती है जो फ़ैक्टरी या establishment को नुकसान करे तो maternity benefit नहीं मिलेगा

नौकरी से निकालने का order निकालने के बाद 60 दिन के भीतर appeal कर सकती है एवं वह अथॉरिटी यह निर्णय लेगी की उस महिला को maternity benefit देना है या नहीं एवं उसका निर्णय मान्य होगा।

Sec 13 - जो wages मिल रहे है गर्भवती महिला को उनको नियोक्ता कम नहीं कर सकता। nursing break ले रही ही तब भी नहीं।

Sec 14 - Appointment of inspector

State govt and central govt will appoint inspector. e.g. for Railway central govt; for roadways state govt.

Powers:

- has rights to check register.
- Can take suo-moto action

Employer and women can appeal within 30 days after decision taken by inspector.

The maternity benefit recovery can be done by govt.; money recovery will be done like revenue.

Sec 18 - If an employer granted leave to the women for maternity benefit and if still she came to work the employer can deny her to do work there.

Sec 21 - If an employer didn't pay the maternity benefit and unlawfully fired her in that case he will go for imprisonment for min 3 months and max 1 year and fine will be from Rs. 2000 to up to Rs. 5000. Or both can be done.

Sec 22 - अगर inspector के कार्य में बाधा डालते हैं तो एक साल की सजा एवं 5000 fine.

Sec 23 - Cognisance of offence will be taken by first class magistrate or metropolitan magistrate has the power. This can be done on complaint by inspector or women self or trade union. And it should be done within one year of the incident.

Sec 26 - Power to exempt establishment - if they are giving better benefits as mentioned by govt and govt will exempt the benefit.

Sec 27 - Effect of laws and agreement inconsistent with this act - if maternity benefits are affected from the policies or agreement by the employer then this act should be applied.